



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

No. 99]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 1991/माघ 29, 1912

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 1991/MAGHA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय  
(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)  
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1991

का. आ. 107—तेल क्षेत्र (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 6 (क) की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 अप्रैल, 1987 से खनिज तेलों अर्थात् खनिज तेल और कैसिंग-हेड कंडेसेट पर रायल्टी का दर में वृद्धि करती है और तदनुसार अधिनियम की अनुसूची में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची की मद संख्या 1 और 2 और अ. से संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मर्दे और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं और इन प्रविष्टियों को 1 अप्रैल 1987 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाए, अर्थात् :—

“1. खनिज तेल : तीन सौ चौदह रुपए प्रति मी. टन.

2. कैसिंग हेड कंडेसेट : तीन सौ चौदह रुपए प्रति मी. टन.

[संख्या ओ-120 14/1/91-ओ.एन.जी.डी.-IV]

440GI/91

नोट : — चूंकि संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने में कुछ समय लग गया, अतः रायल्टी की दर में भूतलक्षी प्रभावी तारीख से संशोधन करना आवश्यक हो गया है। तेल उत्पादक राज्यों को लाभ हो रहा है और अन्य राज्यों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum and Natural Gas)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th February, 1991

S.O. 107 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby enhances, with effect from the 1st day of April, 1987, the rate at which royalty shall be payable in respect of the mineral oils, namely, crude oil and casing-head condensate ; and accordingly makes the following

(1)

उपक्रमों के प्रबंध का 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिग्रहण किया गया था और रण्य और बन्द उद्योग विभाग, जो अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कणकला के नाम से जाना जाता है, में परिवर्तन आता है परिवर्तन को "अधिग्रहण विभाग" के रूप में नियुक्त किया गया था।

और यह: केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय देने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वकृत तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति का पश्चात् प्रभावी बना रहे 31 मार्च, 1991 तक की और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए थे। (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेशों से का. आ. 178(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 26 मार्च, 1982, सं. का. आ. 688(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 25 सितम्बर, 1982, सं. का. आ. 384(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 31 मार्च, 1983, सं. का. आ. 936(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./83 तारीख 29 दिसंबर, 1983, सं. का. आ. 469(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./84 तारीख 28 जून, 1984, सं. का. आ. 967(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./84 तारीख 28 दिसंबर, 1984, सं. का. आ. 280(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./85 तारीख 30 मार्च, 1985, सं. का. आ. 144(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./86 तारीख 31 मार्च, 1986, सं. का. आ. 271(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./87, 30 मार्च, 1987, सं. का. आ. 327(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./88, तारीख 30 मार्च, 1988, सं. का. आ. 246(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./89, तारीख 31 मार्च, 1989 और सं. का. आ. 275(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./90, तारीख 30 मार्च, 1990)

और यह: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1992 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 31 मार्च, 1992 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2(3)/80--सी. ए. एस.]

एन. आर. कृष्णन, अपर सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 26th March, 1991

S.O. 213(E)/18AA/IDRA/91.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)/18AA/IDRA/79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order) the management of industrial undertakings known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs. Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary

to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as "Authorised Controller".

And, whereas, the Central Government, being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto 31st March, 1991 (vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development),

Nos. S.O. 178(E)|18A|IDRA|82, dated the 26th March, 1982,

S.O. 688(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982,

S.O. 384(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st May, 1983,

S.O. 936(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th December, 1983,

S.O. 469(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,

S.O. 967(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th December, 1984,

S.O. 280(E)|18A|IDRA|85, dated the 30th March, 1985,

S.O. 144(E)|18A|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,

S.O. 271(E)|18A|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,

S.O. 327(E)|18A|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,

S.O. 246(E)|18A|IDRA|89, dated the 31st March, 1989 and

S.O. 275(E)|18A|IDRA|90, dated the 30th March, 1990;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1992

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of the Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1992.

[File No. 2(3)/80-CUSI]

N. R. KRISHNAN, Addl. Secy.

